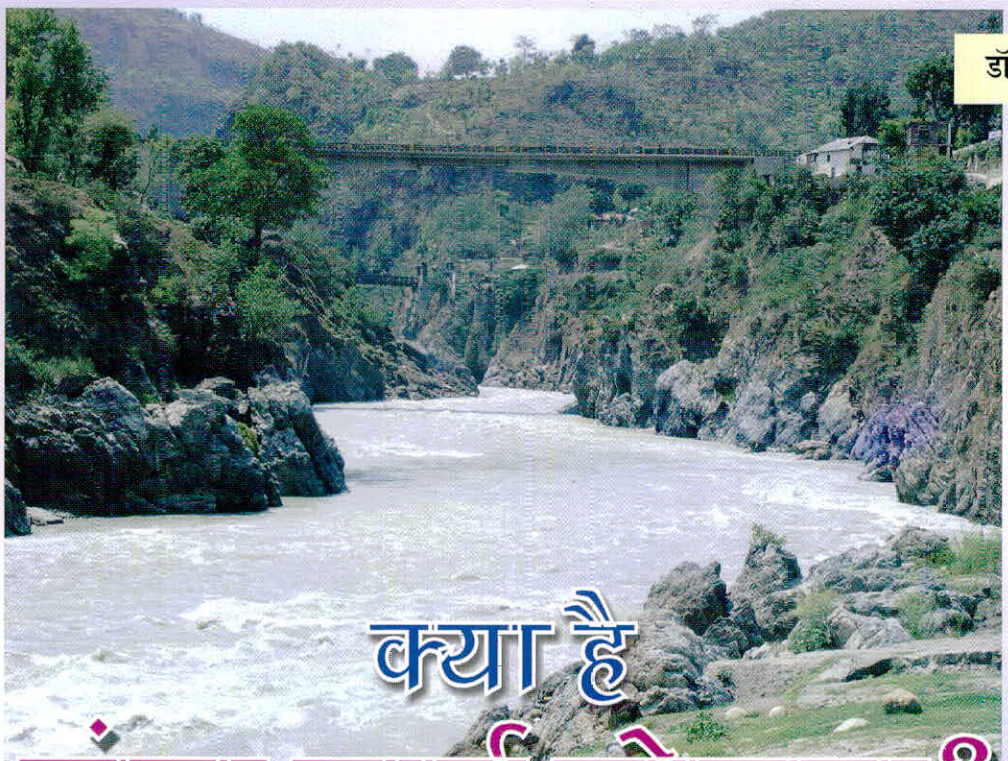

क्या है गंगा कार्य योजना?

डॉ. विजय कुमार उपाध्याय

गंगा जल में बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रख कर गंगा कार्य योजना शुरू करने का विचार सर्वप्रथम भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी के मन में आया था। इसके लिए सन् 1979-80 में एक विस्तृत सर्वेक्षण की योजना बनायी गयी। इस सर्वेक्षण के बाद केन्द्रीय प्रदूषण-नियंत्रण बोर्ड द्वारा दो विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किए गए। ये ही दो प्रतिवेदन गंगा के प्रदूषण-नियंत्रण हेतु गंगा कार्य योजना (गंगा एक्शन प्लान) के आधार बने।

गंगा भारत की सबसे प्रमुख नदी है। यह भारत की राष्ट्रीय नदी भी घोषित की गयी है। इस नदी के किनारे देश के कई प्राचीन नगर स्थित हैं जिनमें प्रयाग, काशी तथा पटना आदि शामिल हैं। इस नदी द्वारा भारत के 11 राज्यों में लगभग 40 प्रतिशत लोगों को जल की आपूर्ति की जाती है।

वर्तमान समय में गंगा काफी प्रदूषित नदी मानी जाती है। लगभग 2.9 अरब लीटर मल जल (सीवेज) प्रतिदिन आकर गंगा में मिल रहा है जिसमें लगभग 20 करोड़ लीटर मल जल सिर्फ वाराणसी में इस नदी में शामिल हो रहा है। गंगा नदी 29 ऐसे बड़े नगरों से होकर गुजरती है जिनकी जन संख्या एक लाख से अधिक है। जबकि इसके किनारे 23 ऐसे नगर बसे हुए हैं जिनकी जन संख्या 50 हजार से एक लाख के बीच है। इसके अलावा 48 छोटे-छोटे शहर भी गंगा के किनारे बसे हुए हैं। गंगा में मिलने वाला अधिकांश मल जल इन्हीं नगरों के आवासीय मकानों से निकल कर आता है। इसके अलावा गंगा किनारे चमड़े के कई कारखाने, रासायनिक यौगिकों को तैयार करने वाले कारखाने, कपड़े के कारखाने, शराब के कारखाने, कसाई खाने (स्लॉटर हाउस) तथा अस्पताल भी बने हुए हैं। इनसे निकलने वाला मल जल तथा अन्य प्रकार की गंदगी भी गंगा में मिलती रहती है। हालांकि इन कारखानों द्वारा प्रवाहित किया जाने वाला मल जल गंगा में मिलने वाले कुल मल जल का सिर्फ 12 प्रतिशत है, परंतु यह अधिक विषैला है तथा गंगा में स्नान करने वाले लोगों तथा इसमें रहने वाले जलचरों के लिए अधिक घातक है। सन् 1854 में हरिद्वार में गंगा पर एक बांध बनाया गया जिसके कारण इसकी धारा की गति में काफी ह्रास आ गया। इसके कारण भी प्रदूषण-स्तर बढ़ता गया।

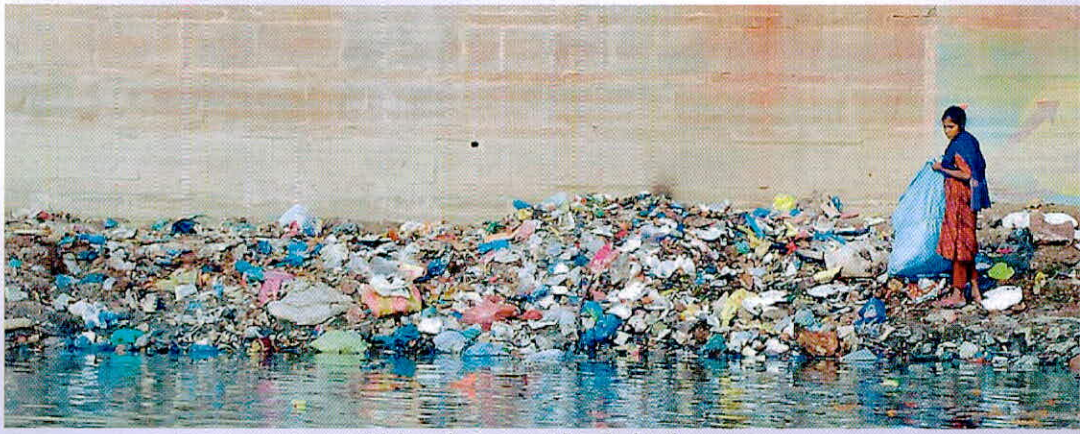

पॉलीथीन एवं कूड़ा-करकट के बढ़ते गंगा में बढ़ता प्रदूषण

नदियों में पूजा सामग्री एवं पुष्प प्रवाहित किए जाने के कारण बढ़ता प्रदूषण

7 जुलाई 2014 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में गंगा मंथन पर राष्ट्रीय संवाद का परिदृश्य

गंगा जल में बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रख कर गंगा कार्य योजना शुरू करने का विचार सर्वप्रथम भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी के मन में आया था। इसके लिए सन् 1979-80 में एक विस्तृत सर्वेक्षण की योजना बनायी गयी। इस सर्वेक्षण के बाद केन्द्रीय प्रदूषण-नियंत्रण बोर्ड द्वारा दो विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किए गए। ये ही दो प्रतिवेदन गंगा के प्रदूषण-नियंत्रण हेतु गंगा कार्य योजना (गंगा एक्शन प्लान) के आधार बने। अप्रैल 1985 में मंत्रिमंडल द्वारा गंगा कार्य योजना को शत प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित घोषित किया गया।

गंगा कार्य योजना संबंधी नीति निर्धारण तथा उससे जुड़े कार्यक्रम की देख-रेख तथा पर्यवेक्षण हेतु सन् 1985 में ही भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण (सेंट्रल गंगा ऑथोरिटी संक्षेप में सी.जी.ए.) का गठन किया गया। आगे चलकर सन् 1985 में ही इस प्राधिकरण का नया नामकरण किया गया 'राष्ट्रीय नदी सरंक्षण प्राधिकरण (नेशनल रीवर कंजरवेशन ऑथोरिटी संक्षेप में एन.आर.सी.ए.) जिसके चेयरमैन पदेन (एक्स औफिसियो) प्रधान मंत्री बनाए गए। सन् 1985 में ही पर्यावरण विभाग के एक अंग के रूप में 'गंगा परियोजना निदेशालय (गंगा प्रोजेक्ट डाइरेक्टोरेट या संक्षेप में जी.पी.डी.) का गठन किया गया जिसे केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण के निर्देशन में गंगा कार्य योजना को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। सन् 1994 में 'गंगा परियोजना निदेशालय का

प्रथम चरण (फर्स्ट फेज) में कुल 69 परियोजनाओं पर कार्य पूरा किया गया। इस दौरान लगभग दस लाख लीटर मलजल प्रतिदिन या तो शुद्ध किया गया अथवा रास्ता बदल कर उसे गंगा में मिलने से रोका गया।

नाम बदल कर नया नामकरण किया गया 'राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय (नेशनल रीवर कंजर्वेशन डाइरेक्टोरेट या संक्षेप में एन.आर.सी.डी.)।

गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण (फर्स्ट फेज) के कार्यान्वयन की शुरूआत 14 जनवरी 1986 को हुई तथा 31 मार्च, 2000 को इसे समाप्त घोषित किया गया। इस कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य था आवासीय मकानों तथा कई प्रकार की औद्योगिक इकाइयों से निकलकर गंगा में मिलने वाले मल जल (सीवेज) तथा कुछ विषैले रसायनिक प्रदूषकों को रोकना, उनके रास्ते को बदलना तथा रासयनिक उपचारण (कैमिकल ट्रीटमेंट) द्वारा उसमें मौजूद प्रदूषकों को अलग कर देना जिससे सिर्फ शुद्ध जल ही गंगा में मिल सके।

मल जल उपचारण (सीवेज ट्रीटमेंट) के लिए नयी प्रौद्योगिकी का उपयोग किए जाने की योजना बनायी गयी। ऐसी प्रौद्योगिकी में प्रमुख है - अप फ्लो अनऐरोबिक स्लज ब्लैंकेट (जिसे संक्षेप में यू.ए.एस.बी. कहा जाता है)। साथ ही मल जल आने वाले रास्ते में वृक्षारोपण की योजना भी बनायी गयी जिससे मल जल का अधिकांश भाग इन वृक्षों द्वारा शोषित कर लिया जाए। इसके अलावा कोमल आवरण वाले (शॉफ्ट शेल्ड) कछुओं के पुनर्वास का लक्ष्य भी रखा गया। क्योंकि इस प्रकार के कछुए प्रदूषण को दूर करने में काफी सहायक पाए गए हैं। इस कार्य योजना में गंगा का प्रदूषण दूर करने के अलावा मीथेन उत्पादन के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करने तथा मछली पालन का भी लक्ष्य रखा गया।

प्रथम चरण (फर्स्ट फेज) में कुल 69 परियोजनाओं पर कार्य पूरा किया गया। इस दौरान लगभग दस लाख लीटर मल जल प्रति दिन या तो शुद्ध किया गया अथवा रास्ता बदल कर उसे गंगा में मिलने से रोका गया। प्रथम चरण के कार्यान्वयन पर लगभग नौ अरब रूपए खर्च किए गए। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण द्वारा गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण में किए गए कार्यों के दौरान आने वाली विभिन्न समस्याओं तथा उस दौरान प्राप्त किए गए अनुभवों का आंकलन तथा मूल्यांकन किया गया जिससे कि इन अनुभवों का लाभ दूसरे चरण के कार्यान्वयन के दौरान उठाया जा सके।

भारत सरकार द्वारा गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण (सेंकड फेज) की स्वीकृति कई चरणों में दी गयी जिसकी शुरूआत सन् 1993 में ही हो गयी थी तथा बहुत बाद तक चलती रही। गंगा कार्य योजना के इस चरण में गंगा के अलावा उसकी सहायक नदियों को भी शामिल किया गया जिनमें प्रमुख थीं - यमुना, दामोदर तथा महानंदा। प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो तरीके अपनाए जाने की योजना बनायी गयी उनमें शामिल थे - (1) मल जल को या तो रास्ते में रोकना अथवा उसका रास्ता बदल देना, (2) मल जल के उपचारण (ट्रीटमेंट) हेतु उपकरणों की स्थापना, (3) कम खर्च की सैनिटेशन सुविधा का निर्माण तथा (4) विद्युत शवदाह गृहों या विकसित किस्म के काष्ठ शवदाह सुविधा का निर्माण।

आजकल गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण पर काम चल रहा है। अब तक लगभग दस अरब से अधिक रूपए खर्च किए जा चुके हैं तथा 1064 एम.एल.डी. (मिलियन लीटर पर डे) मल जल के उपचारण (ट्रीटमेंट) की सुविधा का निर्माण पूरा किया जा चुका है। सन् 2006 में गंगा जल के प्रदूषण के माप संबंधी एक प्रतिवेदन तैयार किया गया जिसमें बताया गया कि प्रति 100 मिली गंगा जल में फेकल कोलिफॉर्म 10 करोड़ एम.पी.एन. (मोस्ट प्रोबेबुल नंबर) तथा बी.ओ.डी. (बायोलॉजिकल ऑक्सीजन

गंगा के सफाई अभियान में जुटी आम जनता - एक ठोस पहल

गंगा के सफाई अभियान में जुटे साधु समाज एवं अन्य श्रद्धालुओं का योगदान

डिमांड) 40 मिलीग्राम प्रतिलीटर है।

गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण से संबंधित एक परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा 10 जून, 2010 को दी गयी थी। यह परियोजना वाराणसी में जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी के सहयोग से नेशनल गंगा रीवर बेसिन ऑथोरिटी की देख-रेख में चलायी जा रही है। इस परियोजना पर कुल 496.90 करोड़ रूपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। इस खर्च का 85 प्रतिशत भाग (लगभग 427.73 करोड़ रूपए) केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि शेष 15 प्रतिशत भाग (अर्थात् 69.17 करोड़ रूपए) राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना में प्रदूषण-नियंत्रण के साथ-साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले गंदे जल (एफ्लुएंट) का उपयोग सिंचाई हेतु किया जाएगा।

राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण (नेशनल गंगा रीवर बेसिन ऑथोरिटी) के निर्देशन में विश्व बैंक की सहायता से गंगा के प्रदूषण नियंत्रण हेतु चलने वाली एक परियोजना की स्वीकृति सन् 2011 में दी जा चुकी है जिस पर लगभग 70 अरब रूपए खर्च आने का अनुमान लगाया गया है। इसमें विश्व बैंक द्वारा एक अरब अमरीकी डॉलर की सहायता प्रदान की जाएगी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है प्रदूषण निबंत्रण हेतु बुनियादी ढ़ांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर) का निर्माण। विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत उपर्युक्त राशि में से 80.1 करोड़ डॉलर इंटरनेशनल बैंक फॉर रीकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द्वारा कर्ज के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। जबकि शेष 19.9 करोड़ अमरीकी डॉलर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य स्तर पर संस्थानीय ढ़ांचे को निर्मित करने तथा उसे मजबूती प्रदान करने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही एक गंगा ज्ञान केन्द्र (गंगा नोलेज सेंटर) की स्थापना की जाएगी।

गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए हाल में समाज के कुछ जागरूक लोगों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने का सशक्त प्रयास किया है। सन् 2011 के प्रारंभ में स्वामी निगमानंद सरस्वती नामक एक संत ने हरिद्वार जिले में गंगा के आस-पास गैर कानूनी उत्खनन (माइनिंग) को रोकने हेतु आमरण अनशन किया। इस अनशन के कारण जून 2011 में उनकी मृत्यु हो गयी। उनकी मृत्यु के बाद उनके आश्रम के प्रधान संत स्वामी शिवानंद ने 25 नवंबर, 2011 को अनशन शुरू किया जो 11 दिनों तक चला। इससे उत्तराखंड सरकार हरकत में आयी और हरिद्वार जिले में गैर कानूनी उत्खनन पर रोक लगा दी गयी। आई.आई.टी. कानपुर के भूतपूर्व प्राध्यापक डॉ. जी.डी. अग्रवाल ने भी गंगा प्रदूषण को राकने हेतु काफी लंबे समय तक अनशन किया जिसका समर्थन अन्ना हजारे जैसे

सन् 2014 के संसदीय चुनाव के बाद जब श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भारत के प्रधान मंत्री का पद संभाला तो उन्होंने गंगा की सफाई तथा उससे बढ़ते प्रदूषण को प्रभावी ढ़ंग से नियंत्रित करने का निश्चय किया। इसी उद्देश्य से 'नमामि गंगा' नाम की परियोजना शुरू करने की घोषणा जुलाई 2014 में की गयी।

सामाजिक कार्यकर्त्ता ने किया। भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने डॉ. जी. डी. अग्रवाल की मांग पर विचार करने तथा आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।

सन् 2014 के संसदीय चुनाव के बाद जब श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला तो उन्होंने गंगा की सफाई तथा उसके बढ़ते प्रदूषण को प्रभावी ढ़ंग से नियंत्रित करने का निश्चय किया। इसी उद्देश्य से 'नमामि गंगा' नाम की परियोजना शुरू करने की घोषणा जुलाई 2014 में की गयी। इसके लिए 10 जुलाई, 2014 को वित्त मंत्री श्री अरूण जेठली जी द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में 6300 करोड़ रूपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया। इस रकम में से 2037 करोड़ रूपए गंगा की सफाई तथा प्रदूषण-नियंत्रण हेतु खर्च किए जाएंगे, तथा 4200 करोड़ रूपए नेविगेशन कौरीडोर के विकास पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा लगभग 100 करोड़ रूपए घाटों के विकास तथा उसके सौंदर्यीकरण पर खर्च किए जाएंगे। रकम जुटाने हेतु 'एन.आर. आई.फंड' बनाया जाएगा जिसके अंतर्गत विदेशों में कार्यरत भारतीयों से धन प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। 'नमामि गंगा' परियोजना को लागू करने की दिशा में प्रथम कदम के रूप में गंगा किनारे स्थापित 48 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है।

संदर्भ :

(1) वन इंडिया न्यूज, 10 जून, 2010
(2) प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सूचना, 9 अगस्त, 2011
(3) विकीपीडिया (पोल्युशन ऑफ गैंजेज)

संपर्क करें :

डॉ. विजय कुमार उपाध्याय
राजेन्द्र नगर हाउसिंग कॉलोनी,
के.के. सिंह कॉलोनी, पो.-जमगोड़िया,
वाया-जोघाडीह, चास, जिला-बोकारो,
झारखंड, पिन कोड : 827013

नया वर्ष

नया वर्ष इस तरह उदय हो।
जीवन का हर सुख अक्षय हो।

नए-नए हों स्वप्न, हृदय में नव आशाएं।
घर-आंगन में सुख के तरूवर, झूमें, गाएं।
मदन-मस्त हो चलें हवाएं, मन महकाएं।
नए-नए अनुभव जीवन में सुख बरसाएं।

धर्म और संस्कृति अजय हो।
नया वर्ष इस तरह उदय हो।

कोई कहीं अभाव नहीं हो, सुखद भाव हो।
सबके मन में अपनापन हो, क्यों दुराव हो।
नई-नई हो मित्र कल्पना, नया चाव हो।
लहरों पर इठलाती बहती हुई, नाव हो।

हर प्राणी, हर जीव अभय हो।
नया वर्ष इस तरह उदय हो।

सुगम-सरल हो मार्ग, राह में नहीं घात हो।
जीवन में हर लक्ष्य प्राप्त हो, नव प्रभात हो।
भय का वातावरण नहीं हो, मुदित गात हो।
बाधारहित चले जीवन, ज्यों जल-प्रपात हो।

दुःख पर सुख की सदा विजय हो।
नया वर्ष इस तरह उदय हो।

गत से भी ज्यादा सुंदर हो, आगत अपना।
पूरा हो जो भी देखा हो, हमने सपना।
हो प्रकाशमय जीवन, व्याप्त कभी हो तम-ना।
सुख-शांति-समृद्धि कहीं हों किंचित कम-ना।

तप्त नहीं हो, तृप्त हृदय हो।
नया वर्ष इस तरह उदय हो।

जहां-जहां पर पड़े सूर्य की, प्रथम यह किरण।
वहां-वहां मां लक्ष्मी के भी पड़े, शुभ चरण।
सुख-शांति ऐश्वर्य, संपदा नहीं हो क्षरण।
मेरी शुभकामना करे यों सभी का वरण।

सबको शुभकामना सदय हो।
नया वर्ष इस तरह उदय हो।

जल संचय

आओ जल का संचय कर लें।
बरखा की बूंदों को बांधे,
सागर की लहरों को बांधे,
धरती पर निर्झर की बांधे,
नदियां ओर सरोवर बांधे,
मन में ऐसा निश्चय कर लें।
आओ जल का संचय कर लें।
रोकें व्यर्थ बहाना जल का।
पानी खुला न छोड़ें नल का।
रोकें छत से पानी ढलका।
चिन्तन करना होगा कल का।
निश्चित मन में आशय कर लें।
आओ जल का संचय कर लें।
व्यर्थ एक भी बूंद नहीं हो।
कुछ भी आंखें मूंद नहीं हो।
जल-जीवन में खूंद नहीं हो।
मन में पड़ी फफूंद नहीं हो।
भावों में भावोदय कर लें।
आओ जल का संचय कर लें।
नए-नए हम वृक्ष लगाएं।
जंगल अब कटने ना पाएं।
प्रकृति से भी प्रीत निभाएं।
जीव-जंतु जीवित रह पाएं।
अपना भी आत्मोदय कर लें।
आओ जल का संचय कर लें।
निर्मित हों तालाब सरोवर।
नदियां भी हों देश धरोहर।
जन-साधारण को हैं सुखकर।
जीवित रहते इनमें जलचर।
जन-जीवन सर्वोदय कर लें।
आओ जल का संचय कर लें।
वृक्ष कटें मौसम बदलेंगे।
बादल भी राहें भूलेंगे।
खेतों में फिर क्या बो लेंगे।
प्यासे-प्यासे हम डोलेंगे।
वृक्ष लगा भाग्योदय कर लें
आओ जल का संचय कर लें।
जल भारत का जन-मन-गण है।
यह किसान का जीवन धन है।
छुपा इसी में अपनापन है।
जल के बिना धरा निर्धन है।
वृक्ष लगा ग्रामोदय कर लें।
आओ जल का संचय कर लें।

संपर्क करें :

श्री हितेश कुमार शर्मा, गणपति भवन, सिविल लांइस, बिजनौर -246701(उत्तर प्रदेश)